



Adhunik Samachar

आधुनिक भारत का आधुनिक नजरिया

आधुनिक समाचार

प्रयागराज से प्रकाशित एवं सम्पूर्ण भारत वर्ष मे प्रसारित



रुद्धि इश्वराम् ये



आई.टी.आई में सीधे प्रवेश NAINI INDUSTRIAL TRAINING CENTRE

(Govt. Affiliated, Star Graded, Record Holder, ISO Certified Training Centre)

नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के प्रवेश कार्यालय का हुआ उद्घाटन



नैनी। नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के प्रवेश कार्यालय का हुआ उद्घाटन भारत सरकार द्वारा मान्यता पास नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र प्रवेश कार्यालय का सिविल डिफेंस प्रयागराज के मंडल अधिकारी रौनक गुसा के द्वारा किया गया प्रशिक्षण केंद्र के प्रवेश प्रभारी मोहम्मद कौसर ने बताया कि प्रयागराज में न्यूनतम शुल्क मुद्दों प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। यहां इंडस्ट्रियल विजिट सेमिनार, ग्रुप डिस्क्यूशन, आदि कराया जाता है जिसे प्रशिक्षणार्थीयों का सर्वानिंदिन विकास होता है। केंद्र गुणवत्ता परिषद द्वारा स्टार गेंडिंग प्राप्त है। केंद्र के कंप्यूटर शिक्षक रोहित शुक्ल ने बताया कि सरकार द्वारा छात्रवृत्ति एवं टैबलेट की सुविधा उपलब्ध है प्रशिक्षणार्थीयों को प्रशिक्षण के दौरान सरकार द्वारा मार्ड भी दिया जाता है प्रशिक्षणार्थीयों को प्रशिक्षण के दौरान सरकार द्वारा मार्ड भी दिया जाता है। मुख्य अतिथि ने नवीन प्रवेशार्थीयों का स्वागत एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है प्रयागराज नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण के द्वारा रौनक गुसा। इस अवसर पर निरीक्षक विजय पांडे, रोहित शुक्ला, सदिन श्रीवास्तव, मोहम्मद कौसर, प्रदीप जायसवाल आदि लोग उपस्थित रहे।



नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के छात्र रेलवे में चयनित



नैनी। नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के चार छात्रों का सिक्कदराबाद में रेलवे में चयनित होने पर संस्थान परिवार ने बधाई दी है। प्रयागराज करचना तहसील के नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के चार छात्रों का रेलवे के धारा रेल प्रोजेक्ट सिक्कदराबाद में चयन होने से विद्यालय प्रबंधतंत्र द्वारा छात्र का सम्मान एवं अभिनन्दन किया। इस अवसर पर संस्थान के प्रवेश प्रभारी मोहम्मद कौसर ने इन छात्रों का समारोहपूर्वक अभिनन्दन एवं सम्मान करते हुये कहा कि यह विद्यालय के लिये गौरव की बात है संस्थान के शिक्षक सदैव इस बात पर बल देते हैं कि छात्र अच्छा रीखें और अपने भविष्य को उज्ज्वल एवं सफल बनावें। उन्होंने भविष्य में और मेहनत व लगन से अध्यापन व अध्ययन करने हेतु शिक्षकों और छात्रों का आङ्गन किया। इस अवसर पर केक काटकर केंद्र का स्थापना दिवस भी मनाया गया।

Admission Open 2024-25



श्री सत्यदेव दुबे (प्रधानाचार्य)
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भदोही



श्री सुजीत श्रीवास्तव (प्रधानाचार्य)
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नैनी, प्रयागराज



इ. अर्चना सरोज (द्रेनिंग एवं पलेसमेन्ट, अधिकारी
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खागा, फतेहपुर

- ★ C.O.P.A.
- ★ Fitter
- ★ Computer Teacher Training
- ★ Electrician
- ★ Fire Safety & Industrial Security
- ★ Repair of Refrigerator & A.C.
- ★ Welding Technology
- ★ Certificate in YOGA
- ★ Security Service
- ★ Computer Hardware & Maintenance

Naini ITC Honored by U.P. State Industrial Association

JEEVAN EXPRESS NEWS

PRAYAGRAJ: A seminar was organized by Uttar Pradesh State Industrial Association on Friday. In which Naini Industrial Training Center was honored with a citation by the association's president Arvind Rai for providing high quality skilled workers. Mohammad Kausar received the honor from the Centre. On this occasion, all the entrepreneurs of Prayagraj including Arinnd Rai Sheetal Plastics, Anat Chandra Ventura Private Limited, BLKHN Engineering Works, S Shukla, Overseas Food Agro Private Limited, union officials and all the industrialists were present.



Visit us at www.nainiiti.com Call: 9415608710, 7459860480



मिहारा

सोनभद्र

बच्चों ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) सोनभद्र। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस पर बृहस्पतिवार को प्रकाश जीवनियस पट्टिक इमिश स्कूल

कि यह दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि जनसंख्या नियंत्रण सहित जनसंख्या मुद्दों पर प्रकाश डाला जा सके। इसकी स्थापना दुरिया

राबटर्सेंज सोनभद्र में जनसंख्या

दिवस मनाया गया। विद्यालय में

विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का

आयोजन किया गया जिसमें छात्रा

अनुका सिंह और काजल ने

भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर

सभी को अधिक जनसंख्या से होने

वाली समस्याओं के बारे में बताया

तथा पैंटिंग एवं स्मूचे प्रतियोगिता

के माध्यम से अब्र छात्रों से हो

रहे अब्रादी से होने वाली समस्याओं

को दर्शाया

इस प्रतियोगिता में

प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-

छात्राओं को विद्यालय के प्रबंधक

राजेंद्र प्रसाद जैन द्वारा पुरस्कृत

किया गया। उन्होंने विद्यालय के

बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा

कि आबादी से जुड़ी विवादों को

दूर करने के लिए कोई गई है। इसमें

विद्यालय के मुख्य कार्यकारी

अधिकारी संतोष कुमार पांडे ने

बताया कि यह दिवस जनसंख्या

सहित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने

और जनसंख्या के नकारात्मक

प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने

के के लिए एक जनसंख्या

कार्यक्रम बृद्धि से कोई जनसंख्या

वर्तायी नहीं होती है। पर्यावरण

पर दबाव एवं सांसद्यों पर दबाव

पड़ता है। इसके कम करने की

आवश्यकता है त इस अवसर पर

विद्यालय के प्रबंधक

राजेंद्र प्रसाद जैन द्वारा पुरस्कृत

किया गया। उन्होंने विद्यालय के

बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा

कि यह दिवस जनसंख्या

के बारे में जागरूकता फैलाने

के के लिए एक जनसंख्या

कार्यक्रम बृद्धि से कोई जनसंख्या

वर्तायी नहीं होती है। पर्यावरण

पर दबाव एवं सांसद्यों पर दबाव

पड़ता है। इसके कम करने की

आवश्यकता है त इस अवसर पर

विद्यालय के प्रबंधक

राजेंद्र प्रसाद जैन द्वारा पुरस्कृत

किया गया। उन्होंने विद्यालय के

बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा

कि यह दिवस जनसंख्या

के बारे में जागरूकता फैलाने

के के लिए एक जनसंख्या

कार्यक्रम बृद्धि से कोई जनसंख्या

वर्तायी नहीं होती है। पर्यावरण

पर दबाव एवं सांसद्यों पर दबाव

पड़ता है। इसके कम करने की

आवश्यकता है त इस अवसर पर

विद्यालय के प्रबंधक

राजेंद्र प्रसाद जैन द्वारा पुरस्कृत

किया गया। उन्होंने विद्यालय के

बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा

कि यह दिवस जनसंख्या

के बारे में जागरूकता फैलाने

के के लिए एक जनसंख्या

कार्यक्रम बृद्धि से कोई जनसंख्या

वर्तायी नहीं होती है। पर्यावरण

पर दबाव एवं सांसद्यों पर दबाव

पड़ता है। इसके कम करने की

आवश्यकता है त इस अवसर पर

विद्यालय के प्रबंधक

राजेंद्र प्रसाद जैन द्वारा पुरस्कृत

किया गया। उन्होंने विद्यालय के

बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा

कि यह दिवस जनसंख्या

के बारे में जागरूकता फैलाने

के के लिए एक जनसंख्या

कार्यक्रम बृद्धि से कोई जनसंख्या

वर्तायी नहीं होती है। पर्यावरण

पर दबाव एवं सांसद्यों पर दबाव

पड़ता है। इसके कम करने की

आवश्यकता है त इस अवसर पर

विद्यालय के प्रबंधक

राजेंद्र प्रसाद जैन द्वारा पुरस्कृत

किया गया। उन्होंने विद्यालय के

बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा

कि यह दिवस जनसंख्या

के बारे में जागरूकता फैलाने

के के लिए एक जनसंख्या

कार्यक्रम बृद्धि से कोई जनसंख्या

वर्तायी नहीं होती है। पर्यावरण

पर दबाव एवं सांसद्यों पर दबाव

पड़ता है। इसके कम करने की

आवश्यकता है त इस अवसर पर

विद्यालय के प्रबंधक

राजेंद्र प्रसाद जैन द्वारा पुरस्कृत

किया गया। उन्होंने विद्यालय के

बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा

कि यह दिवस जनसंख्या

के बारे में जागरूकता फैलाने

के के लिए एक जनसंख्या

कार्यक्रम बृद्धि से कोई जनसंख्या

वर्तायी नहीं होती है। पर्यावरण

पर दबाव एवं सांसद्यों पर दबाव

पड़ता है। इसके कम करने की

आवश्यकता है त इस अवसर पर

विद्यालय के प्रबंधक

राजेंद्र प्रसाद जैन द्वारा पुरस्कृत

किया गया। उन्होंने विद्यालय के

बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा

कि यह दिवस जनसंख्या

के बारे में जागरूकता फैलाने

के के लिए एक जनसंख्या

कार्यक्रम बृद्धि से कोई जनसंख्या

वर्तायी नहीं होती है। पर्यावरण

पर दबाव एवं सांसद्यों पर दबाव

पड़ता है। इसके कम करने की

आवश्यकता है त इस अवसर पर

विद्यालय के प्रबंधक

राजेंद्र प्रसाद जैन द्वारा पुरस्कृत</p

सम्पादकीय

चुनौतियों के बीच बेहतर कर प्रशासन के अवसर पहचानना जरूरी, तर्कसंगत बनेगी व्यवस्था

यह सच है कि जीएसटी में किसी राज्य के हित से ज्यादा राष्ट्रीय हितों को तवज्जो दी गई है। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) से प्राप्त आय का प्रबंधन भी एक बड़ा विषय है। पचास प्रतिशत आईजीएसटी मूलतः वितरण के लिए केंद्र द्वारा समर्पित राज्य राजस्व है। यह कर वस्तु एवं सेवाओं के अंतरराज्यीय आवाजाही के बदले वसूला जाता है, इसलिए इसे आपूर्ति की जगह/राज्य के अनुसार वितरित किया जाना चाहिए। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भारतीय कराधान के इतिहास में एक ऐतिहासिक कर सुधार रहा है। यह अब सात साल पुराना हो चुका है। एक जुलाई, 2017 को शुरू होने के बाद से इसे लेकर उम्मीदें बढ़ी ही हैं। जीएसटी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसने कर व्यवस्था को अधिक कुशल और सरल बना दिया है। हालांकि विभिन्न संकमणकालीन चर्नौतियों के बार-बार कम हो रहा हो पूरक पहले ज्यादातर कर उत्पादन के आधार पर थे, इसलिए कर राजस्व का ज्यादा हिस्सा उत्पादक राज्यों द्वारा अर्जित किया जाता था। अब चूंकि जीएसटी गंतव्य पर आधारित है, इसलिए कर राजस्व उन राज्यों को मिलता है, जहां उपभोग होता है। इससे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे गरीब, उपभोक्ता राज्यों को मदद मिलती है। हालांकि जिन राज्यों को इससे राजस्व में हानि की आशंका थी, उन्हें केंद्र सरकार ने पांच साल तक मुआवजा दिया। मुआवजा बंद करने के बाद भी राज्यों के राजस्व में कोई बड़ी कमी नहीं हुई। मतलब जीएसटी राजस्व राज्यों में सुव्यवस्थित हो गया है। हालांकि, भारतीय जीएसटी एक ऐसा मॉडल है, जो इतने बड़े कर सुधार की जटिलातों और उनके बाद के समाधान को दर्शाता है। फिर भी कर ढांचे के कुछ पहलू जीएसटी की सरलता के बादों के विपरीत हैं।

कारण थोड़ा संदेह भी पैदा हुआ है। अप्रत्यक्ष कर पारंपरिक रूप से सरकारों के लिए कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। लंबे समय तक अप्रत्यक्ष कर को राजस्व के साधन के रूप में देखा जाता था, न कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले साधन के रूप में। नतीजतन लंबे समय तक यह पुराने ढंग से चलता रहा, जिसमें कोई सुधार न हुआ। 1970 के दशक के बाद गठित विभिन्न समितियों ने इनमें व्यापक सुधार की सिफारिश की, जिनमें से कुछ को लागू किया गया। बाद में अप्रत्यक्ष कर में कई बदलाव हुए, जो अंततः 2005 में मूल्य वॉर्डल कर (वैट) के रूप में सामने आए। जीएसटी उसी वैट प्रणाली का विस्तार है। जीएसटी में तकनीक का भी व्यापक उपयोग किया गया है। पूरा जीएसटी नेटवर्क इस पर निभर है। ई-वे बिल इस तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, व्योंकि यह वस्तुओं की आवाजाही को कर प्रशासन की नजर में रखता है। इसके अलावा ये बिल आपूर्तिकर्ताओं के जीएसटी रिटर्न में स्तरः शामिल हो जाते हैं, जिन्हें पहले मैनुअली जांचना पड़ता था। चूंकि अब सब कुछ ऑनलाइन है, तथा ई-वे बिल का प्रारूप पूरे देश में एक जैसा है, इसलिए पारगमन दस्तावेजों की जांच में लगने वाला समय घट जाता है तथा विभिन्न राज्यों में अलग-अलग प्रक्रियाओं से पैदा होने वाली उलझन भी खत्म हो जाती है। जीएसटी का एक लाभ यह भी है कि इससे क्षेत्रीय असमानताएं ह। इसालए, कई मामला म परिणाम अपेक्षा से कम रहे हैं। जीएसटी, कर दरों और विभिन्न छूटों से संबंधित नियम अब भी बदल रहे हैं, जिससे पिछले सात वर्षों में जीएसटी के प्रदर्शन का समग्र आकलन करना कठिन है। फिर भी शुरुआती आंकड़ों से कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। हालांकि जीएसटी ज्यादा व्यवसायों को कर के दायरे में लाने में सफल रहा है, लेकिन उन्हें करों का भुगतान करने के लिए बाध्य करने का काम अब भी बाकी है। जीएसटी से कर प्रशासन पर दबाव बढ़ा है, क्योंकि छोटे व्यवसायी कुल पंजीकृत लोगों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, फिर भी उनका वास्तविक कर योगदान अपेक्षाकृत नगण्य है। तर्क दिया जाता है कि इन करदाताओं को छोड़ दिया जाए, प्रशासन को उच्च बोझ से राहत दिलाई जाए और बड़े करदाताओं को बेहतर सुविधा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इसके लिए पंजीकरण सीमा को सावधानीपूर्वक निर्धारित करने की जरूरत है, ताकि अधिक लोग इसमें शामिल न हों। अन्य विशेषता यह है कि छोटे व्यवसायों का कर अनुपालन बढ़ा है। लेकिन शोध से पता चला है कि छोटी कंपनियों को अपने परिचालन में?ज्यादा अनुपालन लागतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि छोटी कंपनियों के लिए कंपोजिशन स्कीम (जिसमें छोटे व्यवसायी नियमित जीएसटी दरों के बजाय निश्चित कर दरों का विकल्प चुन सकते हैं।) लाया गया है।

टैक्स छूट से बढ़ेगी खरीदारी-खपत जीडीपी में तेजी का कारण बनेगी रियायत

मध्यरर्ग का दी गई टैक्स छट खरीदारी की शक्ति में बाजारों में आएगी और फिर खपत बढ़ेगी, जो जीड़ीपी में तेजी का कारण बनेगी। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण एक आइटमों की खरीदारी करके भारतीय टैक्स भी दे रहा है। वह अच्छी शिक्षा पाने के लिए अपने बच्चों को? विदेशी कॉलेज-यनिवर्सिटी में भेजता है और भारतीय बैंकों के

जाए, क्योंकि आयकर देने वाला जीएसटी भी दे रहा है। कुछ मामलों में तो करदाता कुल मिलाकर 50 फीसदी टैक्स दे रहा है। फिर भी उसे अपने बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा है, उसे सरकार अपने काम में लगाती है। सरकार को 80 डी की सीमा में भी बढ़ोतरी करनी चाहिए। यह मेडिकल खर्च से जुड़ा हुआ है, जिसकी सीमा लंबे समय से नहीं



तैयारी में है। लोकसभा चुनाव से पूर्व उन्होंने जो अंतरिम बजट पेश किया था, वह भले ही संतुलित बजट था, लेकिन उसमें मध्यवर्ग को कोई राहत नहीं दी गई थी। अब जब वह पूर्ण बजट पेश करने वाली है, तो लोगों, खासकर मध्यवर्ग की उनसे उम्मीदें बढ़ गई हैं, क्योंकि फिलहाल वह राहत देने की स्थिति में है। यह मध्यवर्ग ही है, जो बड़े पैमाने पर खरीदारी करवें अर्थव्यवस्था की रफ्तार बनाए रखने में मदद करता है। वित्तमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि देश में बढ़ती खपत के कारण ही जीडीपी में तेजी दिख रही है। उन्होंने माना कि खपत बढ़ने से कारखानों की भी रफ्तार बढ़ जाती है, जिससे रोजगार बढ़ता है, जो अंततः लोगों की क्रयशक्ति बढ़ाकर खपत को बढ़ावा देता है। आज भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग भी इसी वर्ग के बूते फल-फूल रहा है। यही नहीं, देश का उच्च मध्यवर्ग लगजरी

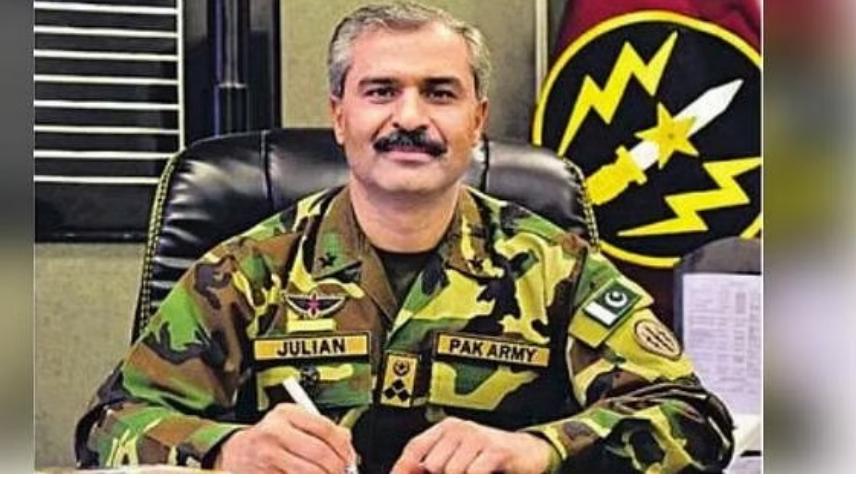
है। मध्यवर्ग का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान उल्लेखनीय है, इसलिए वह सरकार से कुछ प्रोत्साहन की उम्मीद रखता है। इस बार सरकार की उम्मीदों से कहीं ज्यादा टैक्स की वसूली हुई है। प्रत्यक्ष और परोक्ष करों में आशातीत बढ़ोत्तरी हुई है। जीएसटी वसूली बढ़कर हर महीने औसतन पौने दो लाख करोड़ रुपये तक जा पहुंची है। दूसरी ओर आयकर में वसूली भी बढ़ गई है। यानी सरकार के पास राहत देने के लिए काफी गुणजड़ा है। वित्तमंत्री चाहें, तो आयकर दरों में कटौती कर सकती है, जिसकी मांग लंबे समय से हो रही है। मध्यवर्ग और निम्न-मध्यवर्ग के समक्ष आयकर एक बड़ी बाधा है, जो उसकी खर्च करने की क्षमता को सीमित कर रहा है। देश में महंगाई बढ़ने से लोगों को घर चलाने में दिक्कतें आ रही हैं। जनता की मांग है कि पुरानी आयकर दर को घटाकर 5 से 20 फीसदी कर दिया

ही है। टैक्स में कटौती करने से उनकी खपत करने की ताकत? भी बढ़ेगी। कुछ कारोबारियों का सुझाव है कि सभी प्रकार के टैक्स हटाकर एक देश-एक टैक्स की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी बैंक लेन-देन कर प्रणाली लागू करनी चाहिए, ताकि कर अनुपालन में लगने वाले समय को बचाकर उसे कारोबार में लगाया जा सके। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वित्तमंत्री 80 सी की सीमा बढ़ाए। वर्ष 2014 में तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इसे बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये कर दिया था, जिससे करदाताओं को फायदा हुआ था। पिछले दस साल में महाराष्ट्र इतनी बढ़ गई कि अब इसका भी ज्यादा फायदा नहीं हो पा रहा है। इसलिए 80 सी की सीमा को बढ़ाकर दो लाख रुपये कर देना चाहिए। गौरतलब है कि 80 सी में लगाया गया धन सरकार के भी काम आता है। लोग पैसीएफ, एनएससी वैरह में जो निवेश करते काफी बढ़ातेरी हुई है। साथ ही चिकित्सा बीमा पर लगने वाले 18 फीसदी जीएसटी को भी कम करना चाहिए, क्योंकि बीमा कंपनियों ने अपने प्रीमियम अनाप-शनाप तरीके से बढ़ा दिए हैं। इस बजह से लाखों लोग बीच में ही स्तास्य बीमा छोड़ देते हैं। बीमा को लोकप्रिय बनाने के लिए जरूरी है कि उसकी प्रीमियम पर टैक्स घटे। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजित होगा। अभी सरकार का खजाना भरा हुआ है और आने वाले समय में इसमें कुछ और बढ़ातेरी होगी। इसलिए वित्तमंत्री लोगों की मांगें पूरी कर सकती हैं। इतिहास गवाह है कि टैक्स दर घटाने से टैक्स वसूली नहीं घटती। जीडीपी बढ़ाने के लिए यह जरूरी है, क्योंकि मध्यवर्ग को दी गई टैक्स छठ, खरीदारी की शक्ति में बाजारों में आएगी और फिर खपत बढ़ेगी, जो जीडीपी में तेजी का कारण बनेगी।

अल्पसंख्यक आयोग का गठन आशावादी पहल मुल्क विभाजन के बाद असुरक्षा का मावना ध्वजानक, पर दोस्तों व परिवार के साथ संपर्क हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, होता है। इससे पहले एक और

का आबादी का 23 फॉस्टदो हस्सा अल्पसंख्यक यानी गैर-मुस्लिम था। अफसोसनाक बात है कि आज यह आंकड़ा घटकर तीन से चार फॉस्टदी मात्र रह गया है। ऐसे में गिनी-चुनी जगहों पर कुछ अल्पसंख्यकों का पहुंचना? पाकिस्तान को सहिष्णु और म रहने का एकमात्र तराका रगान पोस्टकार्ड भेजना था या कोई अपने वरन में किसी से बात करना चाहता था, तो उसे होटल से लैंडलाइन या बाहर किसी सार्वजनिक टेलीफोन बूथ से कॉल बुक करनी पड़ती थी? यह निश्चित रूप से एक अलग

अहमादिया, बहाइ आर अन्दर
शामिल हैं। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सद्व्यव बनाने के लिए एक
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग गठित
किया है। इसलिए जब मेजर
जनरल जुलियन जेम्स सेना के
विशेष सेवा समूह में दो-सितार



नहीं। यह महिलाओं के एक समूह की सच्ची दास्तां है, जिसने एक बेहद ज़रुरी छुट्टी पर जाने का फैसला किया। लोकेन छुट्टी पर समूह में जाने की एक शर्त थी, जिस पर यात्रा से पहले सबको सहमत होना था। शर्त यह थी कि यह छुट्टी फोन मुक्त होगी। किसी को भी मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं थी। यदि कोई तस्वीरें लेना चाहती है, तो उसे अपने साथ पारंपरिक कैमरा लेकर जाना होगा या वे डिस्पोजेबल कैमरा से फोटो ले सकती हैं, जो अब बेहद आम है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिन महिलाओं को अपने मोबाइल फोन की लत थी, उन्हें बातचीत की कला सीखनी पड़ी? वास्तव में उन्हें एक-दूसरे से बातचीत करनी पड़ी और हमेशा एक्स (टिवटर) या इंस्टाग्राम पर संदेश भेजने से वंचित रहना पड़ा। ऐसा करना सबके लिए आसान नहीं होता, क्योंकि लोगों को मोबाइल फोन की इतनी ज्यादा लत लग गई है कि वे रात में अपने बिस्तर के बगल में टेबल पर फोन रखते हैं। क्या किसी को याद है कि कैसे दशकों पहले जब लोग विदेश

पहले गैर-मुस्लिम बने, तो इसे एक बड़ी उपलब्धि माना गया। उनकी पदोनन्ति के बाद एक टिप्पणी में कहा गया, 'सरकारी हल्कों में महत्वपूर्ण माना जाने वाला यह मील का पत्थर न केवल मेजर जनरल जेम्स के लिए व्यक्तिगत जीत का प्रतीक है, बल्कि जाति और पंथ से परे प्रदर्शन और योग्यता को पुरस्कृत करने की सशस्त्र बलों की प्रतिवेद्धता का भी उदाहरण है।' ऐसी घटनाएं अक्सर नकारात्मक आख्यानों को चुनौती देती हैं और ज्यादा आशावादी नजरिया पेश करती हैं। ऐतिहासिक रूप से, धार्मिक असहिष्णुता से प्रेरित घटनाओं ने पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों के बीच असुरक्षा की भावना को बढ़ाया है-एक ऐसी भावना, जो मूल्क के विभिन्न हिस्सों में हाल ही में हुई मजहबी हिस्सा की घटनाओं से और भी ज्यादा तेज हो गई है। हालांकि, मेजर जनरल जेम्स की पदोनन्ति इस विपरीत धारणा को सार्वजनिक रूप से पूछ करती है कि सेन्य और सरकारी सेवाओं में अल्पसंख्यक समहों के प्रति पर्ण स्थीकृति, उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर प्रोनेन्ट किया गया था। जब मुझे उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला, तब वह काकुल सेन्य एकडमी से पास ही हुए थे। लेकिन सबसे दिलचस्प इंटरव्यू पाकिस्तानी सेना में शामिल होने वाले पहले सिख अधिकारी का था। वह सिख अधिकारी हैं हरचरण सिंह, जो पाकिस्तानी सेना में मेजर के पद पर कार्यरत है। लेकिन दिलचस्प तथ्य यह भी है कि पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक मुल्क का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने के लिए मुसलमान होना जरूरी है। पाकिस्तान में गैर-मुस्लिम प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जैसे सूरीच धर्मों पर कभी आसीन? नहीं हो सकते। अच्छी बात है कि पाकिस्तानी सेना में शामिल होने के लिए इस तरह के नियम व विनियम आवश्यक नहीं हैं। किसी गैर-मुस्लिम के सेना प्रमुख बनने पर सांविधानिक रोक नहीं है, कम से कम इस मामले में पाकिस्तानी सेना सहिष्णु और लोकतांत्रिक है, हालांकि तथ्य यह भी है कि मूल्क में अब तक कोई गैर-मुस्लिम सेना



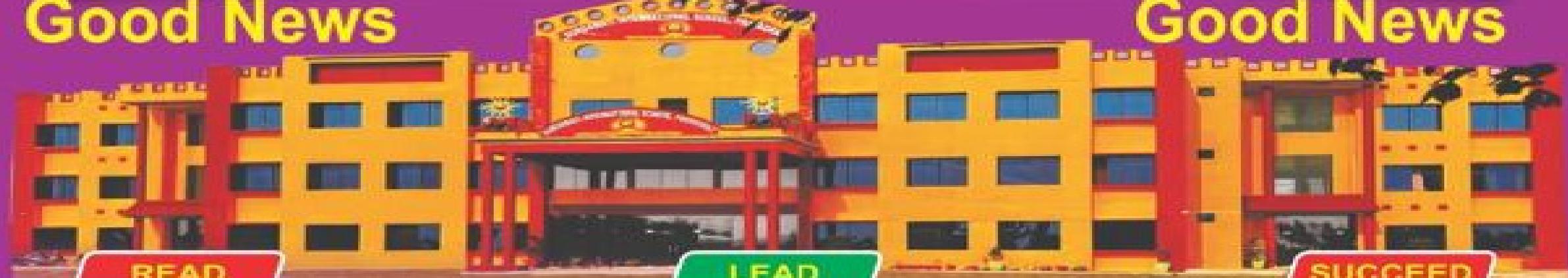
DURGAWATI INTERNATIONAL

School & College Meja, Prayagraj



(AFFILIATED TO NEW DELHI I.C.S.E. (AFFILIATION No. UP 481)

Good News



Good News

THE STUDENTS SCORING ABOVE 95% IN THE ENTRANCE EXAM ARE AWARDED WITH THE CONCESSION IN THE ENTIRE TUITION FEES OF THE WHOLE YEAR 2024-25 HURRY UP!!

HOSTEL FACILITY

- ★ AC hostel facilities are available for the boys from class 3rd onwards.
- ★ Quality food
- ★ Personal care
- ★ 24/7 power backup
- ★ Special tuition classes for hostellers
- ★ Free health checkup per month.
- ★ Infirmary facility is also available
- ★ Well equipped laboratories and digital Library

पहले 50 छात्रों के प्रवेश शुल्क पर 100% की छूट

Admissions
OPEN

PG to IX, XI

(AFFILIATED TO NEW DELHI ICSE
(AFFILIATION No. UP 481)

SCHOOL FACILITIES

- ★ Affordable fee & High-tech infrastructure.
- ★ Spacious and colorful classrooms.
- ★ Trained teachers from Kerala & Prayagraj.
- ★ Free personality development.
- ★ English spoken classes for each student.
- ★ RO water and CCTV facilities.
- ★ Pick and drop facilities with full safety.
- ★ Trained PE Teacher along with
- ★ Spacious playground

Manager

Dr. (Smt.) Swatantra Mishra
(Psychologist)



Email : www.disaldd@gmail.com Durgawati International School

Call For Any Enquiry 7505561664

Contact No.: 7081152877, 7652002511, 9415017879

अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन, सोनभद्र की अध्यक्षता में पुलिस लाइन चुर्क सोनभद्र में आयोजित की गयी नक्सल समन्वय गोष्ठी
(आधुनिक सामाचार नेटवर्क)

सोनभद्र | पुलिस लाइन सभागार कक्ष में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन सोनभद्र श्री त्रिभुवन नाथ प्रियांठी की अध्यक्षता में नक्सल समन्वय गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में जननद के पुलिस/पीएसी/अन्य विभागों व सीमावर्ती जनपदों से आये अधिकारीगण के साथ नक्सली संचरण के दृष्टिकोण सरकारी बहादुरी के बाहरी विभागों व सीमावर्ती जनपदों से आये अधिकारीगण के साथ वार्ता कर उड़े किसी के हाथों में न आने व संदिध गतिविधि होने पर उसकी जानकारी स्थानीय पुलिस व प्रशासन को देने के बारे में जागरूक किया गया एवं अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की गयी। इस दौरान राजकुमार उप सेनानायक



भारतीय जहाज के कप्तान और चालक दल ने बहादुरी के लिए जीता पुरस्कार, लाल सागर बचाव अभियान में दिखाया था कौशल

लंदन। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) ने समुद्र क्षेत्र में बहादुरी के लिए 2024 पुरस्कारों में

बहादुरी, नेतृत्व और दृढ़ संकल्प के लिए सराहना की है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) ने समुद्र क्षेत्र में बहादुरी के लिए अपने 2024 पुरस्कारों में

बहादुरी, नेतृत्व और दृढ़ संकल्प के लिए सराहना की है। अंतरराष्ट्रीय नाविकों को असाधारण बहादुरी और साहस को पुरस्कृत किया गया है। आईएमओ परिषद ने 10 जुलाई 2024 को अपनी कार्यवाही में कैटन अविनाश रावत और ऑपल टैकर मार्लिन लुआंडा के चालक दल की उनकी असाधारण बहादुरी के लिए सराहना की है। चालक दल के प्रयास, जो सेना बलों की सहायता से महत्वपूर्ण समर्थन के साथ, चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने, जहाज को बचाने और ऑपल टैकर मार्लिन लुआंडा के चालक दल की उनकी असाधारण

भारतीय नाविकों की असाधारण बहादुरी और साहस को पुरस्कृत किया गया है। आईएमओ परिषद ने 10 जुलाई, 2024 को अपनी कार्यवाही में कैटन अविनाश रावत और ऑपल टैकर मार्लिन लुआंडा के चालक दल की उनकी असाधारण

नेपाली संसद में विश्वास मत सीपीएन-यूएमएल ने भारत से मैत्रीपूर्ण संबंध को लेकर कही बड़ी बात

काठमाडू। नेपाल में प्रधानमंत्री शुक्रान को सदन में विश्वास मत का सामना करने से पहले नेपाली कांग्रेस और सीपीएन-यूएमएल ने

द्विषय जारी कर दिया है। दोनों पार्टियों ने अपने सांसदों से सदन में उपस्थित रहने और विश्वास मत प्रस्ताव में प्रचंड के विरुद्ध मतदान करने का कहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल प्रचंड को द्विषय का कांग्रेस के साथ समझौता किया गया है। केंद्रीय शर्मा ओली की अगुआई वाली सीपीएन-यूएमएल ने पिछो सापाह प्रचंड सरकार से समर्थन वापस ले लिया और गठबंधन सरकार बनाने के लिए नेपाली कांग्रेस के साथ समझौता किया गया है। केंद्रीय शर्मा ओली की अगुआई वाली नेपाल की कांग्रेस-यूएमएल से समझौता क्या? क्षर्सावाली लेनिवादी (सीपीएन-यूएमएल) ने गुरुवार को कहा कि चौतरफा भूमि से दिया हमारा देश केवल भारत से घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखकर ही आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर सकता है। पार्टी ने जार देकर कहा कि वह नेपाल की भूमि से पड़ोसी देश के विरुद्ध किसी गतिविधि की अनुपत्ति नहीं देगा। पार्टी के विदेश मामलों के विभाग प्रमुख एवं स्थायी समिति के सदस्य डा. राजन भट्टाराई ने शुक्रान को संसद में होने जा रहे विश्वास मत से पहले कहा कि नेपाल की प्रगति संभव नहीं। केंद्रीय शर्मा ओली की अगुआई वाली सीपीएन-यूएमएल का मानना है।

स्वत्वाधिकारी एवं मुद्रक डा. दीपक अरोग द्वारा श्री आधुनिक प्रिन्टर्स

एड एंड प्रेक्झर्स प्राफ़िल.

1-सिर्जन्युपोर्ट रोड नैमी प्रयागराज

उ.प्र. 211008 से मुद्रित एवं

आधुनिक समाचार

पब्लिसिंग हाउस सी 41

यूपीएसआर्डीसी नैमी प्रयागराज

211010 (उ.प्र.)

से प्रकाशित

समाचार/प्रकाशक

डा. पुनीत अरोग

मो००० ०९४१५६०८७१०

RNI No. UPHIN/2015/63398

website: www.aduniksamachar.com

नोट:- इस समाचार पत्र में

प्रकाशित समस्त समाचारों के

चयन एवं सम्पादन हैं तु

पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत

उत्तराधीय तथा इसे उपलब्ध समस्त

विवाद इलाहाबाद न्यायालय के

अधीन ही होते हैं।